सिविल अपील

चीफ जस्टिस हरबंस सिंह और जस्टिस बी.आर.तुली

अपीलकर्ता - राम नारायण शर्मा आदि

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य आदि

1972 का एल.पी.ए. नंबर 460

22 मई, 1973

पंजाब पंचायत समिति को सदस्यों का विकल्प नियम 1961 नियम 4 शब्द "कोरम"-का अर्थ-19 सदस्यों वाली पंचायत समिति की पहली बैठक-बैठक में 14 सदस्यों की उपस्थिति-क्या कोरम बनता है। यह माना गया कि पक्षी कोरम स्पष्ट रूप से सदस्यों की न्यूनतम संख्या को इंगित करता है जिन्हें किसी भी व्यवसाय को स्थानांतरित करने के लिए सदस्यों के हकदार होने से पहले किसी विशेष बैठक में उपस्थित होना पड़ता है।

यह माना गया कि 19 सदस्यों वाली पंचायत समिति में इसकी पहली बैठक में 14 सदस्यों की उपस्थिति पंजाब पंचायत समिति (सह-विकल्प सदस्य) नियमों के नियम 4 (1) की बैठक के भीतर कुल गठित मंच की तीन चौथाई नहीं होगी। 1961 इस भूमिका और नियम 4(4) में प्रयुक्त भाषा में अंतर को देखते हुए भी विधानमंडल द्वारा नियम 4(1) में जोड़े गए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, कोरम शब्द के साथ सामान्य अर्थ जोड़ा जाना चाहिए, जिसका मूल

विचार यह है कि किसी बैठक में किसी भी व्यवसाय को कानूनी रूप से करने के लिए वर्णित संख्या न्यूनतम है। जब 19 सदस्यों वाली समिति में ऐसी संख्या 14 1/4 हो जाती है, तो यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि विधानमंडल का इरादा 14 की संख्या तय करने का था, जब तक कि वह इरादा बिल्कुल स्पष्ट न हो। केवल यह तथ्य कि उप-नियम (4) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, केवल अत्यधिक सावधानी के कारण हो सकता है और किसी भी तरह से इस तथ्य को नकारात्मक नहीं करेगा कि पहली बैठक में कोरम 14 से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए।

1972 की सिविल रिट संख्या 2551 में माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. सी. जैन द्वारा पारित 6 अक्टूबर, 1972 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील।

याचिकाकर्ताओं के वकील चंद्र सिंह।

प्रतिवादी की ओर से डी.एस. लांबा, उप-महाधिवक्ता, हरियाणा।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था :-

चीफ जस्टिस हरबंस सिंह - हरबंस सिंह, सी.जे. - यह आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित दो अपीलों (1972 का एल.पी.ए. 460 और 1973 का एल.पी.ए. 49

का निपटारा करेगा) ने दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, एक राम नारायण और दूसरी और दूसरी बहादुर द्वारा दायर की गई थी। राम और अन्य, जो कानून का समान प्रश्न उठाते हैं।

(2) साल्हावास और डबवाली की पंचायत समितियों में, जिनमें से प्रत्येक में 19 निर्वाचित सदस्य हैं, महिला सदस्यों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी शामिल करना था। दोनों समितियों की इस उद्देश्य से आयोजित बैठकों में केवल 14 सदस्य उपस्थित थे और कोरम को उचित मानते हुए सह-विकल्प बनाया गया। इसके विरुद्ध, दो रिट याचिकाएँ (सी. डब्ल्यूएस. 2551 और 2615 सन् 1972) दायर की गईं।

(3) पंजाब पंचायत समितियाँ (सदस्यों का सह-विकल्प) नियम, 1961 (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 4 में निम्नानुसार प्रावधान हैं: -

"4. कोरम

(1) तीन-चौथाई सदस्य व्यक्तियों के सह-विकल्प के लिए कोरम का गठन करेंगे;

(2) यदि पहली बैठक में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कोरम मौजूद नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित कर देगा।

(3) जब उप-नियम (2) के तहत एक बैठक स्थगित कर दी जाती है, तो प्राथमिक सदस्यों को तीन दिन का स्पष्ट नोटिस देकर सदस्यों को सहयोजित करने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी द्वारा एक और बैठक बुलाई जाएगी।

(4) प्राथमिक सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं दूसरी बैठक के लिए कोरम का गठन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.-जहां एक पंचायत समिति में उन्नीस प्राथमिक सदस्य होते हैं, वहां दस सदस्यों से दूसरी बैठक के लिए कोरम पूरा होगा।

(5) यदि दूसरी बैठक में उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रियो कोरम मौजूद है, तो पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित कर देगा।

(6) जब कोई बैठक उप-नियम (5) के तहत स्थगित कर दी जाती है, तो सदस्यों को सहयोजित करने के उद्देश्य से, पीठासीन अधिकारी द्वारा उप-नियम (3) में निर्दिष्ट तरीके से तीसरी बैठक बुलाई जाएगी।

(7) तीसरी बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह था कि जिस संबंधित बैठक में सह-विकल्प हुआ था वह पहली बैठक थी और इसलिए, किसी भी लेनदेन के लिए कानूनी रूप से हकदार होने से पहले तीन-चौथाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। सदस्यों के सह-विकल्प के संबंध में, कि सदस्यों की कुल संख्या 19, तीन-चौथाई 14/1 हो जाती है और बैठक में केवल 14 सदस्य उपस्थित होने से, कोई कोरम नहीं था और इसलिए, उचित रूप से गठित बैठक नहीं हुई।

(5) नियम 4 के उप-नियम (4) को ध्यान में रखते हुए, जहां प्रयुक्त शब्द "आधे से कम नहीं" हैं और इस उप-नियम में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि जहां 19 सदस्य हैं, वहां 10 सदस्य कोरम बनाएंगे दूसरी बैठक के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहली बैठक के मामले में, आधे से कम का अंश, जो इस मामले में केवल एक-चौथाई था, को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और वह एक पंचायत समिति में 19 सदस्यों में से 14 सदस्यों से कोरम पूरा होगा। इसी निर्णय के विरुद्ध ये दो अपीलें दायर की गई हैं।

(6) 'कोरम' शब्द स्पष्ट रूप से उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या को इंगित करता है जिन्हें किसी भी व्यवसाय को करने के हकदार होने से पहले किसी विशेष बैठक में उपस्थित होना पड़ता है। इस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) और (4) में प्रयुक्त अलग-अलग भाषा के लिए, इस निष्कर्ष की कोई गुंजाइश नहीं होती कि यदि निर्धारित कोरम में एक अंश शामिल है, तो वह अंश यदि यह आधे से कम हो तो इसे

नजरअंदाज कर देना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि, क्योंकि उप-नियम (1) में उल्लिखित शब्द हैं "तीन-चौथाई सदस्य व्यक्तियों के सह-विकल्प के लिए कोरम का गठन करेंगे" और उप-नियम (4) में यह कहा गया है "कम नहीं" प्राथमिक सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य दूसरी बैठक के लिए कोरम का गठन करेंगे", उप-नियम (1) के तहत तीन चौथाई सदस्यों की गणना करते समय, एक चौथाई के एक अंश को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का कोई औचित्य नहीं था। यह आग्रह किया गया कि यद्यपि उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में प्रयुक्त शब्द थोड़े भिन्न हैं और मसौदा तैयार करने की सामान्य प्रथा यह है कि यदि एक ही विचार व्यक्त करना है, तो समान शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, फिर भी, 'कोरम' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया विचार "न्यूनतम संख्या" है जो सदस्यों द्वारा कोई भी व्यवसाय करने से पहले मौजूद होना चाहिए। इसलिए, जब कुल सदस्यों की संख्या का तीन-चौथाई निर्धारित कोरम है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि तीन-चार न्यूनतम संख्या है। यह अधिक तो हो सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड 74 में दी गई 'कोरम' शब्द की परिभाषा निम्नलिखित है : -

"शब्द 'कोरम', जो अब आम उपयोग में है, लैटिन से है और किसी भी निकाय के अधिकारियों या सदस्यों की इतनी संख्या को दर्शाता है, जो व्यापार करने के लिए कानून या संविधान द्वारा सक्षम है;

* * * * * *

किसी निकाय का कोरम उसका पूर्ण बहुमत होता है, जब तक कि जिस प्राधिकारी द्वारा निकाय का निर्माण किया गया था, वह इसे एक अलग संख्या में निर्धारित नहीं करता है।

* * * * * *

(8) श्यामापद गांगुली बनाम अबानी मोहन मुखर्जी (1) में, जिसके फैसले पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी गौर किया था, यह माना गया था कि 17 में से दो-तिहाई 11-1/3 पर आते हैं और, परिणामस्वरूप, 11 आयुक्तों द्वारा मतदान नहीं किया गया था पर्याप्त अनुपालन. वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, राज्य की ओर से पेश वकील को कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में दी गई 'कोरम' की परिभाषा या कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में टिप्पणियों के साथ कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन, ध्यान में रखते हुए नियम 4 के उप-नियम (1) और (4) में प्रयुक्त भाषा में अंतर के कारण यह आग्रह किया गया कि विधानमंडल की मंशा यह थी कि 19 सदस्यों वाली सम्पूर्ण पंचायत समिति में 14 सदस्य तीन-चौथाई होंगे। हालाँकि, हमें लगता है कि अगर यही इरादा होता, तो विधानमंडल को उप-नियम (1) में यह

(1) ए.आई.आर. 1951 सीएएल 420.

स्पष्टीकरण जोड़ने से कोई नहीं रोकता था कि जहां एक पंचायत समिति में 19 सदस्य होते हैं, वहां 14 सदस्यों से कोरम पूरा होगा। जब ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, तो 'कोरम' शब्द से सामान्य अर्थ जोड़ना होगा, जिसका मूल विचार यह है कि किसी बैठक में किसी भी व्यवसाय को कानूनी रूप से चलाने के लिए निर्धारित संख्या न्यूनतम है। जब ऐसी संख्या 14,1 पर आती है, तो यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि विधानमंडल का इरादा संख्या 14 तय करने का था, जब तक कि वह इरादा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया हो। केवल यह तथ्य कि उप-नियम (4) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, केवल अत्यधिक सावधानी के कारण हो सकता है और किसी भी तरह से इस तथ्य को नकारात्मक नहीं करेगा कि पहली बैठक में कोरम 14 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। वास्तव में, नियमों के नियम 4 में प्रावधान ऐसे मामले के लिए पर्याप्त और सरल प्रावधान करते हैं जहां पहली बैठक में कोरम नहीं है, क्योंकि, तीन दिन का स्पष्ट नोटिस देकर दूसरी बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें कोरम केवल एक ही है। -आधा और यदि दूसरी बैठक में कोरम उपस्थित नहीं है, तो, तीन दिन की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई गई तीसरी बैठक में, सह-विकल्प किया जा सकता है और कोई कोरम निर्धारित नहीं है। सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से 'कोरम' शब्द के मूल विचार को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि इस अनुमान का कोई औचित्य नहीं है कि पहली बैठक में 14 सदस्य कोरम बनाएंगे। हालाँकि उप-नियम (1) और (4) में प्रयुक्त भाषा में कुछ अंतर

है, फिर भी, वास्तव में, प्रयुक्त शब्दों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। उप-नियम (1) कहता है कि तीन-चौथाई कोरम का गठन करेगा, जिसका अर्थ है कि न्यूनतम संख्या तीन-चौथाई होनी चाहिए और यदि यह तीन-चौथाई से कम है तो कोरम नहीं होगा। उप-नियम (4) में प्रयुक्त शब्द हैं "प्राथमिक सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं कोरम का गठन किया जाएगा", जिसका अर्थ बिल्कुल वही है। (9) उपरोक्त के मद्देनजर, इसलिए, हम इन दो अपीलों को स्वीकार करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हैं, और 1972 के सिविल रिट संख्या 2551 और 2615 को स्वीकार करते हुए और नियम को पूर्ण बनाते हुए, की कार्यवाही को रद्द करते हैं। दोनों पंचायत समितियों में से किसी एक की पहली बैठक, जिसमें उचित कोरम न होने के कारण केवल 14 सदस्य उपस्थित थे। अब इन दोनों समितियों के पास बैठक को फिर से बुलाने और कानून के अनुसार सदस्यों को एक बार फिर से शामिल करने का अधिकार होगा। संपूर्ण लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा